

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-----

No--- 8

Dated ---- 9-9-2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.0744 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ESTABLISHMENT NO. 22 CHAKRATA (D. J. N.) (Name of user agency) for Water Supply Line Along Chakrata Funi Road from Jodi to Chakrata (Purpose for diversion of forest land) in Dehra Dun District falls within jurisdiction of village(s) in Chakrata tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.... Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha (s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure..... to..... Annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)


जिलाधिकारी
देहरादून।

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-----

No--- 7

Dated ---- 9.9.2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.0744 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ESTABLISHMENT NO 22 Chakrata (name of user agency) for Water Supply Line Along Chakrata Puni Road From Jodi to Chakrata (purpose for diversion of forest land) in Dehra Dun district falls within jurisdiction of Chakrata Village in Chakrata tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.... Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha (s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure..... to..... Annexure.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion a copy of certificate issued by the gram sabha of Mungah Villages(s) is enclosed as annexure to annexure.....
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha Present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून।

43

प्रारूप-30.1

परियोजना का नाम :-Water Supply Line along Chakrata, Tyuni Road Jadi to Chakrata of Shifting of existing Pipe Line from Km.70.750 to 72.825 of NH 707A in the State of Uttarakhand.

कार्यवृत्त

प्रक्रांक:- 9 / सक./ वन अधि० अधि० / 2018-19 दिनांक: 9.9.2019

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय-समय पर संशोधित) के धारा-6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं० 11-09/98-FC(Pt) दिनांक 09-08-2000 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 30.8.19 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के संबंध में चर्चा व विचार-विमर्श हुआ।

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत जाडी से चकराता पेयजल योजना के स्थानान्तरण (निर्माण) हेतु 0.0744 है० वह भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु Estt.No.22 Chakrata, Dehradun को वन भूमि हस्तान्तरण:-

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा 6(1) के अनुसार मंगाड (भंगाड) ग्राम पंचायत स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 2.10.18 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की 6(3) के प्राविधानुसार उप जिलाधिकारी चकराता की अध्यक्षता में गठित उप जिला स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 6.8.19 विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में परम्परागत वन निवासी से संबंधित समुदाय का कोई Right व Settlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता

जिलाधिकारी
देहरादून।

जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT --D. Dm. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

Behradum

A meeting of the district level committee of A. district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss C. Ravistankar I.A.S deputy commissioner, on dated 20.8.19, at time at in which application claiming rights in 0.0744 ^{He} area measuring hect for the construction of Water Supply Line forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chakrap sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: D. Dm.
Dated: 9.9.19

Rj
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून

परियोजना का नाम जाडी से चकराता पट्टा लाईन प्रारूप-30.2
कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, _____

उपखण्ड _____ परिक्षेत्र के अन्तर्गत _____ (0.0577) हे० आरक्षित वन भूमि X हे०
सिविल एवं सौयम वन भूमि X हे० वन पचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.0577 हे० वन भूमि) का Est. No 22 Chakrata प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चकराता) की दिनांक _____ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <u>Dr. Apoorva Singh</u>	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री <u>अनुराग कुमार</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री <u>सहायक समाज कल्याण अधिकारी</u>		सदस्य / सचिव
4-	श्री <u>ललीता बी०डी०सी० क्षेत्र</u>	<u>जाडी से चकराता</u>	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की
गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जाडी से चकराता पट्टा लाईन परियोजना हेतु 0.0744 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में
हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।
उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता (वृ० प्रभाग) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पचायत द्वारा
अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।
जाडी से चकराता पट्टा लाईन में सर्वसम्मति से उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु 0.0744 हे० वन भूमि Est. No 22 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित
में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- Chakrata
जनपद- Uttarakhand

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- Chakrata
जनपद- Uttarakhand



परियोजना का नाम :- जाडीस चकराता फाईव लाईन

प्रारूप-30.3

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सुगाड

तहसील - चकराता जिला - देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद 22131 के अन्तर्गत जाडीस चकराता परियोजना के निर्माण हेतु (0.074 हे० आरक्षित वन भूमि, 4 हे० सिविल सोयम भूमि, 4 हे० वन पंचायत भूमि 4 हे०) अर्थात् कुल 0.74 हे० वन भूमि का Est. No 22 विमान/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुगाड द्वारा दिनांक 2-10-18 को सम्मेलन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनमें नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुगाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि Est No 22 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पं. मुमेर
वि.सं. 22131 जनपद देहरादून
मुहर सहित

P/SR

नरेश
कलीया
दोलन

शुभा
Shahan
पताय सिंह

पताय सिंह

सतराम

Bishan Singh पूर्व प्रधान

मुचरा सिंह

